

80/4120

प्रेषक,

डा० राम बिलास यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग-01.

देहरादून: दिनांक 23.08. अक्टूबर, 2017.

विषय: विभागान्तर्गत जनजाति छात्रावासों हेतु अतिरिक्त छात्रावास के भवन निर्माण तथा भवन की मरम्मत आदि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1879/ज.जा.क./बालक छात्रावास/भवन निर्माण/2017-18 दिनांक 04.07.2017 एवं पत्र संख्या-2165/ज.जा.क./बालक छात्रावास/भवन निर्माण/2017-18 दिनांक 31.08.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय जनजाति छात्रावासों में आवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण मद में निम्न तालिका के कॉलम-06 में अंकित धनराशि संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. संख्या-S1710310217 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार रू० 249.28 लाख की धनराशि का वित्तीय एवं प्रशासनीक स्वीकृति प्रदान करते हुए रू० 100.00 लाख (एक करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र.स.	विद्यालय का नाम/कार्य का नाम	आंगणन की धनराशि	निर्माण कार्य	अधिप्राप्ति	योग
1	2	3	4	5	6
1.	राजकीय जनजाति छात्रावास खटीमा जनपद ऊधमसिंह नगर में 50 क्षमता के अतिरिक्त छात्रावास भवन का निर्माण।	239.37	233.62	4.83	238.45
2.	राजकीय जनजाति छात्रावास काशीपुर जनपद ऊधमसिंह नगर में कम्प्यूटर लैब एवं छात्रावास भवनों की मरम्मत, रंगाई पुताई	10.83	10.83	0.00	10.83
योग-		250.20	244.45	4.83	249.28

- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाए जितनी मदवार धनराशि स्वीकृति की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाए।

6. विस्तृत आगणन में प्रावधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
8. समय से उपयोग करने के लिए अवमुक्त धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त करना सुनिश्चित किया जाए।
9. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 वित्तीय नियम संग्रह, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत नियम/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
10. बी0एम0-08 पर संकलित मासिक व्यय की सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
11. निर्माण कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराते हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखे तथा अवमुक्त धनराशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करें।
12. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के लेखाशीर्षक-4225-02-277-05 राजकीय जनजाति छात्रावासों में आवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
13. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30.06.2017 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।


भवदीय,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-334(1)/XVII-1/2017-10(05)/2016, तददिनांक: 30-10-17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
4. एन.आई.सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
5. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Social Welfare (S045)

आवंटन पत्र संख्या 334 /xvii-1/2017-10(05)/2016

अनुदान संख्या - 031

अलोटमेंट आई डी - S1710310217

आवंटन पत्र दिनांक -30-Oct-2017

HOD Name - Director Tribal Welfare (4706)

- 1: लेखा शीर्षक 4225 - अनुसूचित जातियों /जनजातियों तथा अन्य पिछड़े व 02 - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
277 - शिक्षा
05 - राजकीय जनजाति छात्रावासों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण
00 - राजकीय जनजाति छात्रावासों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - बृहत निर्माण कार्य	0	10000000	10000000
	0	10000000	10000000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

10000000